

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष : 01

अंक : 293 :

जौनपुर, मंगलवार 25 जुलाई 2023

सांख्य दैनिक (संस्करण)

पेज - 4

मूल्य : 2 रूपया

उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई स्थगित

एजेन्सी नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। उमर खालिद को 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और बेला एम त्रिवेदी की पीठ से याचिकाकर्ता के वकील ने सुनवाई पर एक सप्ताह की अवधि के लिए स्थगन की मांग की थी। इसके मद्देनजर सुनवाई को स्थगित कर दिया गया। शीर्ष अदालत की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह मामला 9 अगस्त को सूचीबद्ध होने की संभावना



है। उमर खालिद की याचिका के जवाब में दिल्ली पुलिस ने रविवार को जवाबी हलफनामा दायर किया था, जो अभी तक आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड पर प्राप्त नहीं हुआ है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई

को मामले को 24 जुलाई के लिए पोस्ट कर दिया था। दिल्ली पुलिस के वकील ने हजारों पन्नों की चार्जशीट का हवाला देते हुए जवाब पर रिकॉर्ड पर प्राप्त नहीं हुआ है। उमर खालिद की ओर से पेश

हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि वह आदमी दो साल और ग्यारह महीने से हिरासत में है। कौन सा शपथ पत्र दायर करने के लिए है? यह एक जमानत याचिका है। उमर खालिद ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जमानत से इनकार के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मुदुल और रजनीश भटनागर की पीठ ने पिछले साल 18 अक्टूबर को नियमित जमानत की मांग करने वाली उमर खालिद की अपील खारिज कर दी थी। उमर खालिद ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसने उन्हें यूएपीए मामले में जमानत देने से इनकार किया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम

(सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के दौरान अमरावती में दिए गए कथित विवादित भाषण, दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद के खिलाफ आरोपों का आधार थे। दिल्ली पुलिस के अनुसार दंगों से जुड़े कथित बड़े षड्यंत्र मामले में शामिल लगभग एक दर्जन लोगों में जेएनयू स्कॉलर और कार्यकर्ता उमर खालिद, शरजील इमाम शामिल हैं। बता दें फरवरी 2020 में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दंगे भड़क उठे थे। नागरिकता संशोधन अधिनियम विरोधी और सीएए समर्थक प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प ने हिंसक रूप ले लिया था। जिसमें 50 से अधिक लोगों की जान चली गई और 700 से अधिक घायल हो गए थे।

मणिपुर मुद्दे पर संसद में हंगामा, तीसरे दिन भी बगैर काम काज के स्थगित हुई लोकसभा

एजेन्सी नयी दिल्ली। लोकसभा में मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष के भारी हंगामे के कारण सत्र के तीसरे दिन सोमवार को भी कोई कामकाज नहीं हुआ और तीन बार के स्थगन के बाद अध्यक्ष

करने का आग्रह किया और कहा कि सदस्य दो-तीन दिन से लगातार मणिपुर मुद्दे पर चर्चा की बात कर रहे हैं इसलिए इस मुद्दे पर गृहमंत्री सदन में बात रखेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा "मेरा विपक्ष के सभी सदस्यों से

जाए। गृहमंत्री के बयान के बीच भी जब विपक्षी सदस्य नारेबाजी और टोकाटोकी करते रहे। अध्यक्ष बिरला ने कहा "गृहमंत्री का बयान होने दिया जाए। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। हमेशा ऐसे मुद्दों पर संबद्ध विभाग का मंत्री पहले बयान देते हैं हंगामा शुरू कर दिया जिसके कारण उन्हें आधा घंटे के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले सुबह 11 बजे अध्यक्ष ने जैसे ही प्रश्न काल शुरू किया तो विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू करते हुए नारेबाजी आरंभ कर दी और सदस्य आसन के सामने आ



ओम बिरला को सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही चौथी बार हुई बजे अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही शुरू की विपक्षी सदस्य पहले की तरह आसन के सामने आ गये और हंगामा तथा नारेबाजी करने लगे। हंगामा कर रहे सदस्य होंथों में लठ्ठियां थीं। अध्यक्ष ने सदस्यों से हंगामा नहीं

आग्रह है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य इस अत्यंत संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूँ। मालूम नहीं विपक्ष चर्चा क्यों नहीं चाहता है जबकि देश इस पर चर्चा चाहता है। विपक्षी सदस्यों से मेरा आग्रह है कि इस मुद्दे पर चर्चा हो ताकि देश के सामने स्पष्ट संदेश

सावन के तीसरे सोमवार शिवमय हुई संगमनगरी

एजेन्सी प्रयागराज। सावन के तीसरे सोमवार को तीर्थराज प्रयाग शिवमय हो गया। शिवभक्त कांडियों का जत्था गंगा के दशास्वमेध, रामघाट, दारागंज, फाफामऊ एवं संगम घाट पर रनान कर कांड में जल भरकर मनकामेश्वर महादेव, पांडेश्वर महादेव आदि शिवालयों में भक्त जलाभिषेक करने निकल पड़े। श्रद्धालु सुबह से हाथ में जल, फूल, माला, धतूरा, भांग, विल्वपत्र एवं शमी पत्र लेकर

किलोमीटर दूर यमुना किनारे स्थित सुजावन देव मंदिर, दशाश्वेध तक्षकतीर्थ आदि शिवालयों में जलाभिषेक और पूजा-अर्चना करने

विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर परिवार में सुख समृद्धि की कामना के लिए प्रार्थना की। अग्निपुराण में वर्णित अरैल, नैनी सोमेश्वर महादेव की अपनी महिमा है। यहां पर गौतम ऋषि से श्राप मिलने के बाद चंद्रदेव ने इस शिवलिंग की स्थापना की थी। यहां की मान्यता है कि सावन मास में लगातार एक माह तक इस शिवलिंग का जलाभिषेक और दर्शन करने से कुछ रोग ठीक हो जाता है। इसके अलावा ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित दशाश्वमेध घाट,

घूरपुर के भीटा स्थित सुजावन देव, लालपुर स्थित मनकामेश्वर धाम, दरियाबाद स्थित तक्षकेश्वर महादेव की क्षेत्रीय मान्यता है। वैदिक शोध एवं सांस्कृतिक प्रतिष्ठान कर्मकाण्ड प्रशिक्षण केंद्र के आचार्य डा आत्माराम गौतम ने बताया कि हर तीन साल के बाद मलमास लगता है।

यमुना के बाद अब हिंडन भी उफान पर, कई गांवों में घुसा पानी, लाखों लोग हुए प्रभावित

एजेन्सी नोएडा। यमुना नदी में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इसके साथ-साथ हिंडन नदी का जलस्तर भी बढ़ने के चलते गाजियाबाद और नोएडा व ग्रेटर नोएडा के कई गांव में पानी भर गया है और लाखों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने हजारों घरों को भी खाली करवाया है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है। ग्रेटर नोएडा के हैबतपुर, चोटपुर, बहलोलपुर, यूसुफपुर चक शाहबेरी गांव में पानी पहुंचने से करीब 2.50 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने अपनी ओर से हिंडन का जलस्तर बढ़ने का अलर्ट जारी किया है। वही यमुना का जलस्तर भी बढ़ रहा है। गाजियाबाद



के लिए भक्तों की कतारें देखने को मिलीं। सावन के तीसरे सोमवार को कोटेश्वर महादेव मंदिर पर सुबह से शिवभक्तों का पहुंचना शुरू हो गया। भोलेनाथ का जलाभिषेक कर बेलपत्र, फूल-फूल, भांग, धतूरा आदि भोलेनाथ को अर्पित किए। वहीं महिलाओं ने भगवान भोलेनाथ के साथ मां गौरी की

राजस्थान: विधानसभा से मार्शल आउट होने पर फूट-फूट कर रोए राजेंद्र गुड़ा, बोले- मेरी लाल डायरी भी छीन ली

एजेन्सी जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कैबिनेट में मंत्री पद से हटाए जाने के बाद सोमवार को कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह गुड़ा को राजस्थान विधानसभा में प्रवेश नहीं करने दिया गया। वहीं इस दौरान पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा मीडिया से बातचीत के दौरान फूट-फूट कर रोने लगे और आरोप लगाया कि लगभग 50 लोगों ने मुझ पर हमला किया, मुझे मुक्का मारा और लात मारी। रोते हुए गुड़ा ने कहा कि उनसे लाल डायरी भी छीन ली गई। राजस्थान सीएम पर निशाना साधते हुए पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि अगर मैं नहीं होता तो गहलोत जेल

में होते लेकिन उन्हें बर्खास्त करने से पहले सफाई का भी मौका नहीं दिया गया। राजेंद्र सिंह गुड़ा ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने मुझे विधानसभा से बाहर खींच लिया। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष ने मुझे बोलने की अनुमति भी नहीं दी। मेरे खिलाफ आरोप लगाए गए कि मैं भाजपा के बातचीत के दौरान फूट-फूट कर गलती क्या है? गुड़ा ने कहा कि उन्होंने माफी मांगने के बजाए संघर्ष करने का फैसला किया है। साथ ही मारी। रोते हुए गुड़ा ने कहा कि उनसे लाल डायरी भी छीन ली गई। राजस्थान सीएम पर निशाना साधते हुए पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि अगर मैं नहीं होता तो गहलोत जेल

एजेन्सी गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लोगों से धर्मस्थलों, सरकारी व सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षण की अपील की। गोरखनाथ मंदिर के तत्वावधान में अधियारी बाग स्थित मानसरोवर मंदिर में आयोजित सात-दिवसीय (18 से 24 जुलाई) शिव महापुराण कथा के समापन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "दस-ग्यारह वर्ष पूर्व मानसरोवर मंदिर जर्जर और अव्यवस्थित था। समाज की चेतना जागृत हुई और गोरखपुर के श्रद्धालुओं ने संरक्षण का बीड़ा उठाया तो इसका कायाकल्प हो गया।" उन्हीं ने कहा, हर धर्मस्थल, सरकारी व सार्वजनिक संपत्ति को सुंदर रखना सबका कर्तव्य होना चाहिए। यदि किसी सार्वजनिक संपत्ति



को कोई नुकसान पहुंचाता है तो वह धरती माता, अपनी विरासत व पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव ईमानदारी से व्यक्त नहीं कर सकता। इसलिए इन स्थलों को न खुद नुकसान पहुंचाएं और न किसी को नुकसान पहुंचाने दें। योगी आदित्यनाथ ने कहा, "वृहत्तर भारत

में उत्तर से दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम तक श्रद्धालुओं को द्वादश ज्योतिर्लिंगों के माध्यम से अलौकिक ईमानदारी से व्यक्त नहीं कर सकता। इसलिए इन स्थलों को न खुद नुकसान पहुंचाएं और न किसी को नुकसान पहुंचाने दें। योगी आदित्यनाथ ने कहा, "वृहत्तर भारत

मणिपुर हिंसा पर राज्यसभा को जानकारी दें पीएम, सदन में चर्चा और वोटिंग हो : खरग

एजेन्सी नयी दिल्ली। मणिपुर मामले को लेकर राज्यसभा और लोकसभा में सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई है। इसी के चलते मानसून सत्र में अभी तक संसद की कार्यवाही एक भी दिन सुचारु रूप से नहीं चल सकी है। विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर हिंसा को लेकर सदन में अपना बयान रखें, उस बयान पर हम सभी लोग चर्चा करेंगे। चर्चा के बाद इस मुद्दे पर वोटिंग भी कराई जाए। सोमवार को यह बात कांग्रेस अध्यक्ष व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष मलिकार्जुन खरगो ने कही। संसद

में गांधी प्रतिमा के समीप अन्य विपक्षी सांसदों के साथ धरना दे रहे खरगो ने कहा कि जब संसद या विधानसभा का सत्र चल रहा होता है तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री सदन के बाहर बयान नहीं देते। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब बयान संसद के बाहर दिया गया। हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री संसद के भीतर मणिपुर हिंसा की पूरी जानकारी व बयान दें। दरअसल, सरकार व राज्यसभा के सभापति शॉर्ट उच्चरेशन डिस्कशन के लिए राजी हैं। खरगो ने इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि वह कभी आधा घंटा कभी शॉर्ट उच्चरेशन डिस्कशन की बात कहते

मिलती है। व्यासपीठ की पूजा करने के बाद उन्होंने कहा कि पावन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की कथा का आनंद प्राप्त करना सौभाग्य की बात है। शिव महापुराण कथा के समापन में सहभागिता से पहले गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने मानसरोवर मंदिर में रुद्राभिषेक कर सभी नागरिकों के मंगलमय जीवन की कामना की। भोलेनाथ का विधि विधान से दर्शन, पूजन व रुद्राभिषेक करने के उपरांत मुख्यमंत्री ने सभी देव विग्रहों का दर्शन पूजन कर लोक कल्याण की प्रार्थना की। योगी ने कथाव्यास संत बालकदास एवं सभी यजमानों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए देवाधिदेव महादेव से सभी लोगों के सुखमय व समृद्धय जीवन की प्रार्थना की।

मनी लॉन्ड्रिंग केस: एससी से सत्येंद्र जैन को राहत, पांच हफ्ते के लिए और बड़ी अंतरिम जमानत

एजेन्सी नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत की अवधि सोमवार को पांच हफ्ते के लिए बढ़ा दी। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है। जस्टिस ए. एस. बोपन्ना और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की

पीठ को जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने सूचित किया कि 21 जुलाई को उनकी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई थी और उन्हें ठीक होने के लिए समय चाहिए। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने कहा कि वह अंतरिम जमानत बढ़ाने का विरोध नहीं कर

रहे हैं। राजू ने कहा कि जांच एजेन्सी चाहती है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) या किसी अन्य अस्पताल द्वारा जैन के स्वास्थ्य के संबंध में स्वतंत्र जांच का अनुरोध करने वाले उसके आवेदन पर अगली तारीख पर सुनवाई हो। पीठ ने मामले की जमानत बढ़ाने का विरोध नहीं कर

यमुना का जलस्तर फिर खतरे के निशान से ऊपर, 'ओल्ड रेलवे ब्रिज रेल यातायात के लिए बंद

एजेन्सी नयी दिल्ली। यमुना नदी का जलस्तर सोमवार सुबह खतरे के निशान 205.33 मीटर से एक मीटर से अधिक ऊपर रहा, जिसके कारण प्राधिकारियों ने 'ओल्ड रेलवे ब्रिज' (ओआरबी) पर रेलगाड़ियों का आवागमन रोक दिया। ओआरबी पर नदी का जलस्तर 13 जुलाई को 208.66 मीटर के अब तक के सर्वाधिक

ऊंचे स्तर पर पहुंचने के बाद कुछ दिन से खतरे के निशान के आसपास है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद हथिनीकुंड बैराज से नदी में पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया था। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि ओआरबी पर रेलगाड़ियों का परिचालन यमुना के जलस्तर में

बढ़ोतरी के कारण निलंबित कर दिया गया है। अधिकारी ने कहा, "दिल्ली और शाहदरा के बीच मार्ग बंद रहेगा और रेलगाड़ियों को नयी दिल्ली के रास्ते भेजा जाएगा।" अधिकारियों के मुताबिक, नदी के जलस्तर में वृद्धि से राष्ट्रीय राजधानी के बाढ़ प्रभावित निचले इलाकों में राहत एवं पुनर्वास के काम पर असर पड़ सकता है। केंद्रीय जल आयोग

(CWC) के आंकड़ों के अनुसार, यमुना का जलस्तर शनिवार रात 10 बजे 205.02 मीटर से बढ़कर रविवार देर रात तीन बजे 206.57 मीटर पर पहुंच गया। जिसके बाद इसमें गिरावट आने लगी। आंकड़ों के मुताबिक, जलस्तर सोमवार सुबह आठ बजे 206.54 मीटर दर्ज किया गया, जिसके अपराह्न दो बजे तक गिरकर 206.42 मीटर पहुंचने की

संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 25 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। ६ के आंकड़ों के मुताबिक, यमुना नगर स्थित हथिनीकुंड बैराज में जल प्रवाह की दर शनिवार सुबह 9 बजे एक लाख के आंकड़े के पार चली गई।

सम्पादकीय

दावानल बनी मणिपुर हिंसा

उत्तर पूर्व के संवेदनशील राज्य मणिपुर में पिछले तीन महीनों से जारी हिंसा के खिलाफ केन्द्र व राज्य दोनों ही सरकारों के द्वारा वक्त पर कार्रवाई न करने और बेहद लापरवाहीपूर्ण रवये का परिणाम आज इस रूप में सामने आ गया है कि यह आग अब दवानान बन चुकी है। मणिपुर में बिगड़े हालत पिछले सप्ताह जगजाहिर हुए जब एक वीभत्स वीडियो सामने आया था। भला हो सुप्रीम कोर्ट का जिसने स्वतरू संज्ञान लेकर केन्द्र सरकार से 8 दिनों में जवाब मांगा है। उस दिन संसद का सत्र प्रारम्भ होने के पहले पिछले 9 वर्षों से मीडिया से बचने वाले प्रहानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बयान देना पड़ा कि श्वे इस मामले को लेकर क्रोध व पीड़ा से भर गये हैं और किसी भी दोषी को बरखा नहीं जायेगा।प्रधानमंत्री को बयान इसलिये देना पड़ा क्योंकि शीर्ष अदालत ने साफ कहा कि श्वीडियो परेशान करने वाले हैं। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती तो वह कोर्ट कोई कदम उठायेगी।इ इतना बवाल कटने पर भी अब तक 4 लोग ही गिरफ्तार हुए हैं। करीब 80 दिनों की चुप्पी के बाद श्री मोदी ने संसद के भीतर विस्तृत वक्तव्य देने की बजाय संसद भवन के बाहर मामले पर केवल 36 सेकंड का बयान देकर बतला दिया कि पूरे विश्व के सामने देश को शर्मसार करने वाली घटनाओं के प्रति वे न तो संजीदा हैं और न ही इसका सियासी लाभ लेने में चूकेंगे। अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए मोदी ने इसे १140 करोड़ जनता के लिये शर्मनाकश् बताया। पद की प्रतिष्ठा व गरिमा के एकदम प्रतिकूल प्रहानमंत्री ने बड़े हल्केपन से यह भी कहा कि श्छ्तीसगढ़ हो या राजस्थान अथवा मणिपुर, कहीं भी ऐसी हिंसा ठीक नहीं है।इ यह दुखद है क्योंकि इन दोनों प्रदेशों (छग—राज.) के हालात ऐसे बिलकुल नहीं है जिनकी मणिपुर से तुलना हो। दरअसल इन दोनों कांग्रेस शासित राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं जहां भाजपा कमजोर स्थिति में है। अपनी नाकामी को ढंकने के साथ हिंसक घटनाओं का दोनों राज्यों में चुनावी लाभ लेने का यह कुटिल प्रयास है। मणिपुर की सीमा म्यांमार से भी लगती है जहां सैन्य शासन है और वह चीन के प्रभाव में जा रहा है। इस राज्य के रणनीतिक महत्व और मामले की संजीदगी को समझे बिना संसद के बाहर मोदी की ट्रोल आर्मी के सदस्‍यगण, पूर्व केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, मंत्री द्वय स्‍मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर आदि विपक्ष व खासकर कांग्रेस पर टूट पड़े। वैसे भाजपा की नेता उमा भारती ने समझदारी दिखलाते हुए कहा है कि श्दो गलत काम मिलकर एक सही नहीं हो सकते। पिछले कुछ समय से नरेन्द्र मोदी व भारतीय जनता पार्टी का तेजी से गिरता ग्राफ तथा सतत मजबूत होती विपक्षी एकता इस झल्लाहट का राज है। यूरोपियन यूनियन (ईयू) की संसद में चुकी यह मामला उठा ही था, अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भी चिंता जताई है कि मणिपुर में सैकड़ों चर्च जलाये गये हैं व हिंसा हो रही है। देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा और लोगों की धार्मिक आजादी को बाधित करने को लेकर पश्चिमी देशों में भारत की जमकर आलोचना हो रही है। अपनी पिछली विदेश यात्राओं के दौरान भी श्री मोदी को इन सवालों के जवाब देने पड़े हैं। यह अलग बात है कि श्री मोदी, उनकी सरकार और पार्टी को इसके बावजूद धार्मिक—सामाजिक धुंधीकरण के चक्कर में मणिपुर की हिंसा को मौन समर्थन दे रहे हैं। मणिपुर में 4 मई जैसी ही एक और घटना की खबर मिल रही है। मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह पहले ही मान चुके हैं कि ऐसे सैकड़ों मामले वहां हो चुके हैं। वहां की राज्यपाल सुश्री अनुसूईया उइके भी एक समाचार चौनल को बतला चुकी हैं कि राज्य की परिस्थितियां उदावनी हैं और वे इसकी सूचना रूफ़र वालोंश को पहले ही दे चुकी थीं। दूसरी ओर मणिपुर के बहुसंख्यक मैतई मिजोरम में अस्पृक्षित महसूस कर रहे हैं। करीब 10 हजार मैतई मणिपुर व असम लौट गये हैं क्योंकि वहां के पूर्व उग्रवादी संगठन श्पामशाघ ने मैतेइयों को श्स्तकश् रहने को कहा है। यानी हिंसा की सघनता व विस्तार दोनों जारी है। मणिपुर की राज्य समर्थित हिंसा दवानान बन चुकी है। यह अपने उदागम स्थल मणिपुर में तो सघन हो ही रही है, उसकी दहशत पड़ोसी राज्य मिजोरम तक पसर रही है। इस हिंसा का राज्य में पूर्ण शमन तो जरूरी है ही, उसका विस्तार भी रूकना चाहिये।

त्वरित फैसले जरूरी

यह हमारे नीति—नियंताओं के लिये बेहद गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए कि देश की विभिन्न अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या पांच करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। केंद्र सरकार द्वारा गुरुवार को राज्यसभा में बताया गया कि शीर्ष अदालत में सत्तर हजार, उच्च न्यायालयों में साठ लाख से अधिक तथा जिला और अधीनस्थ अदालतों में 4.4 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। निस्संदेह, लंबित मामलों में वृद्धि के अनेक कारण हैं। जिनमें न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की अपर्याप्त संख्या, मामलों के निपटान के लिये निर्धारित समय सीमा का अभाव, बार—बार स्थगन और सुनवाई मामलों की निगरानी व ट्रैक करने के लिये प्रभावी व्यवस्था की कमी प्रमुख हैं। इसके बावजूद इन मुकदमों के लंबित होने के मुख्य कारण को भी तलाशना जरूरी है ताकि न्याय की शह सुगम हो। विगत में पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना ने देश की अदालतों में मुकदमों की लंबी फेरिस्त के लिये विधायी कर्मियों के साथ—साथ कार्यपालिका की निष्क्रियता को भी दोषी ठहराया था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने देश की विभिन्न अदालतों में पचास फीसदी से अधिक लंबित मुकदमों के लिये राज्य मशीनरी की चूक या लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया था। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार की दलील है कि अदालतों में लंबित मामलों का निस्तारण न्यायपालिका का कार्यक्षेत्र है। बहरहाल, तार्किक बात तो यह है कि सभी पक्षों को मिलकर मुकदमों का भारी—भरकम बोझ दूर करने के लिये दृढ़

(2)

मणिपुर की आहट मिजोरम तक

सबसे पहले हर भारतवासी को यह स्पष्ट होना चाहिए कि पूर्वोत्तर के राज्य भारत माता का ऐसा उज्ज्वल माथा हैं जिसके हर हिस्से के हर राज्य ने प्रत्येक परिस्थिति में राष्ट्र की सुरक्षा में आहुति देने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई है। चीन की सीमा से सटे ये राज्य भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की अग्रिम पंक्ति रहे हैं अतः इनमें पूर्ण शान्ति व सौहार्द बनाये रखने के लिए 1947 से ही भारत की हर केन्द्र सरकार ने गंभीर प्रयास किये हैं और इन राज्यों की उग्रवाद व चरमपंथी समस्याओं का निपटारा भी किया है। 2013 तक पूर्वोत्तर के हर राज्य से चरमपंथ या उग्रवाद की समस्या सफलतापूर्वक समाप्त कर दी गई थी और सभी राज्यों के लोग अपने लोकतान्त्रिक अधिकारों का प्रयोग करके अपनी चुनी हुई सरकारों के माध्यम से अपना विकास कर रहे थे। परन्तु विगत मई महीने के शुरु में इन्ही राज्यों में से एक मणिपुर में यहां की दो जनजातियां मैतई व कुकी—जोमो के बीच जो संघर्ष छिड़ा उससे यह राज्य अब गृहयुद्ध की स्थिति में पहुंचता जा रहा है क्योंकि मई से लेकर अब तक जनजातीय संघर्ष

आधुनिकता की दौड़ में विस्मृत होती सनातनी परंपराएं स त्रिशंकु बनकर लटक रहे हैं

संजीव ठाकुर
वर्तमान में आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम इस तरह तेज भाग रहे हैं कि हमारी सनातनी परंपराएं ६ गिरे—धीरे पीछे छूट रही हैं और हम आधुनिकता तथा परंपराओं के बीच त्रिशंकु बंद कर लटक रहे हैं। भारतीय संस्कृति हमें अपने भारतीय होने का एहसास कराती है। जो हमें विश्व के अन्य देशों से विकास की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। भारत में अनेक परंपराएं ऐसी हैं जो सामाजिक जीवन को अधिक सम्य एव अच्छा इसान बनाए रखने में योगदान देती है। जिनसे मनुष्यता का जीवन जीने की प्रेरणा भी मिलती है। यांत्रिक उपकरणों की तरह जिंदगी जीना भी कोई जीना है। यह भारतीय संस्कृति में पाश्चात्य का घालमेल ही है जो मनुष्य के जीवन को यंत्रवत बना देता है। जो आने वाले कल के लिए घातक भी हो सकती है। वहीं दूसरी ओर पाश्चात्य दर्शन की कुछ विशेषताएं भी हैं, जो हमारे विचारों को अधिक तार्किक तथा बौद्धिक बनाती है। जिससे हम अपना जीवन कार्तिक तथा बौद्धिक बना सकते हैं।

संजय गुप्त
मणिपुर उच्च न्यायालय की ओर से राज्य के मैती समुदाय को जनजाति का दर्जा देने पर विचार करने के आदेश के बाद कुकी और इस समुदाय के बीच शांति—सद्भाव अचानक भंग हो गया और वहां मई के पहले सप्ताह में हिंसा भड़क उठी। यह हिंसा दो माह बाद भी पूरी तौर पर शांत नहीं हो सकी है। इस हिंसा के दौरान कुकी और मैती, दोनों ने एक—दूसरे पर हमले किए, उनके घर लूटे—जलाए और हत्याएं भी कीं। इस दौरान पुलिस के हथियार भी लूटे गए और उनका इस्तेमाल हिंसा फैलाने में किया गया। दोनों पक्ष एक—दूसरे पर अत्याचार करने में पीछे नहीं रहे। इसके चलते हजारों लोगों को पलायन करना पड़ा। जब स्थितियां कुछ नियंत्रित होती दिख रही थीं, तो एक ऐसा वीडियो सामने आया, जिसमें कुकी समुदाय की दो महिलाओं को निर्बरत्र कर घुमाया गया। इनमें से एक के साथ सामूहिक दुष्कर्म भी किया गया। यह घटना चार मई की है, लेकिन उसका वीडियो चंद दिन पहले आया। इस घटना ने देश को शर्मसार करने के साथ झकझोर कर रखा। चूंकि यह वीडियो संसद सत्र शुरू होने के पहले आया इसलिए राजनीतिक हंगामा भी शुरू हो गया—संसद में भी और संसद के बाहर भी। मणिपुर की वीभत्स घटना की जितनी भर्त्सना की जाए, कम है। यह घटना दोनों समुदायों यानी मैती और कुकी के बीच की कटुता को तो बताती ही है, यह भी इंगित करती है कि घृणा के शिकार लोग किस हद तक गिर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ठीक ही कहा कि यह सभ्य समाज को शर्मसार करने वाली घटना है और

रखना चाहिए कि इन्ही राज्यों में से एक ‘सिक्किम’ का भारतीय संघ में विलय 1973 के करीब तत्कालीन प्रहानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जब किया था तो यहां के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। उससे पहले सिक्किम एक स्वतन्त्र राजतन्त्र था

से चलते हैं। इनमें से अकेला राज्य नागालैंड ऐसा था जिसमें अंग्रेजी शासनकाल से ही विद्रोही गतिविधियां चल रही थीं। स्वतन्त्र होने के बाद भारत की सरकारों ने इस समस्या का हल भी ढूंढा और 1966 में सभी पूर्वोत्तर राज्यों के समाहित प्रदेश असम को सात राज्यों में विभाजित किया। ऐसा इसलिए किया गया जिससे हर इलाके की आदिवासी व कबीला संस्कृति अपने रंग—रूप में फल—फूल सके। पूरे पूर्वोत्तर में सभी जनजाति के लोग एक—दूसरे के साथ प्रेमभाव के साथ रहते थे और एक— दूसरे की परंपराओं व रीति—रिवाजों का सम्मान भी करते थे। परन्तु मणिपुर में आज जो हम देख रहे हैं उसके लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं क्योंकि इस राज्य के आदिवासी व गैर आदिवासी लोगों के बीच बढ़ते अविश्वास को हमने कम करने का प्रयास नहीं किया। 2012 में

राज्यों पर भी पड़ती दिखाई दे रही हैं। जब किसी भी राज्य के दो समुदायों के बीच अविश्वास पैदा हो जाता है तो वह राज्य और उसकी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था अराजकता की स्थिति में पहुंच जाती है। मणिपुर में हम यही देख रहे हैं। हमें याद

जिन्हें हम अपने जीवन में क्रियान्वित कर अपने मनुष्य जाति के जीवन को अधिक सार्थक एवं सुलभ बना सकते हैं। निस्संदेह हमें रूढ़ीवादी या एकदम पुरातन पंथी संस्कृति से लगाव न रखकर पाश्चात्य संस्कृति के जो फायदे हैं, उन्हें अपनाकर अपना जीवन सरल सार्थक एवं सुगम बना सकते हैं। परंतु आज वर्तमान के अन्य देशों से विकास की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। भारत में अनेक परंपराएं ऐसी हैं जो सामाजिक जीवन को अधिक सम्य एव अच्छा इसान बनाए रखने में योगदान देती है। जिनसे मनुष्यता का जीवन जीने की प्रेरणा भी मिलती है। यांत्रिक उपकरणों की तरह जिंदगी जीना भी कोई जीना है। यह भारतीय संस्कृति में पाश्चात्य का घालमेल ही है जो मनुष्य के जीवन को यंत्रवत बना देता है। जो आने वाले कल के लिए घातक भी हो सकती है। वहीं दूसरी ओर पाश्चात्य दर्शन की कुछ विशेषताएं भी हैं, जो हमारे विचारों को अधिक तार्किक तथा बौद्धिक बनाती है। जिससे हम अपना जीवन कार्तिक तथा बौद्धिक बना सकते हैं।

जिन्हें हम अपने जीवन में क्रियान्वित कर अपने मनुष्य जाति के जीवन को अधिक सार्थक एवं सुलभ बना सकते हैं। निस्संदेह हमें रूढ़ीवादी या एकदम पुरातन पंथी संस्कृति से लगाव न रखकर पाश्चात्य संस्कृति के जो फायदे हैं, उन्हें अपनाकर अपना जीवन सरल सार्थक एवं सुगम बना सकते हैं। परंतु आज वर्तमान के अन्य देशों से विकास की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। भारत में अनेक परंपराएं ऐसी हैं जो सामाजिक जीवन को अधिक सम्य एव अच्छा इसान बनाए रखने में योगदान देती है। जिनसे मनुष्यता का जीवन जीने की प्रेरणा भी मिलती है। यांत्रिक उपकरणों की तरह जिंदगी जीना भी कोई जीना है। यह भारतीय संस्कृति में पाश्चात्य का घालमेल ही है जो मनुष्य के जीवन को यंत्रवत बना देता है। जो आने वाले कल के लिए घातक भी हो सकती है। वहीं दूसरी ओर पाश्चात्य दर्शन की कुछ विशेषताएं भी हैं, जो हमारे विचारों को अधिक तार्किक तथा बौद्धिक बनाती है। जिससे हम अपना जीवन कार्तिक तथा बौद्धिक बना सकते हैं।

जिन्हें हम अपने जीवन में क्रियान्वित कर अपने मनुष्य जाति के जीवन को अधिक सार्थक एवं सुलभ बना सकते हैं। निस्संदेह हमें रूढ़ीवादी या एकदम पुरातन पंथी संस्कृति से लगाव न रखकर पाश्चात्य संस्कृति के जो फायदे हैं, उन्हें अपनाकर अपना जीवन सरल सार्थक एवं सुगम बना सकते हैं। परंतु आज वर्तमान के अन्य देशों से विकास की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। भारत में अनेक परंपराएं ऐसी हैं जो सामाजिक जीवन को अधिक सम्य एव अच्छा इसान बनाए रखने में योगदान देती है। जिनसे मनुष्यता का जीवन जीने की प्रेरणा भी मिलती है। यांत्रिक उपकरणों की तरह जिंदगी जीना भी कोई जीना है। यह भारतीय संस्कृति में पाश्चात्य का घालमेल ही है जो मनुष्य के जीवन को यंत्रवत बना देता है। जो आने वाले कल के लिए घातक भी हो सकती है। वहीं दूसरी ओर पाश्चात्य दर्शन की कुछ विशेषताएं भी हैं, जो हमारे विचारों को अधिक तार्किक तथा बौद्धिक बनाती है। जिससे हम अपना जीवन कार्तिक तथा बौद्धिक बना सकते हैं।

प्रश्न यह भी है कि आखिर खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थीं? चार मई की घटना मणिपुर के माहोल को फिर से खराब सकती है, क्योंकि वह बेहद अचानक और विचलित करने वाली है। आज के जमाने में दो समुदायों में इतना वैमनस्य होना चकित करता है। आया और उसे लेकर हड़कंप मचा। किसी के लिए ए भी समझना कठिन है कि घटना की एफआइआर मई में ही हो जाने के बाद भी पुलिस को कार्रवाई करने में इतना समय क्यों लग गया? मणिपुर के मुख्यमंत्री, जो राज्य के गृहमंत्री भी हैं, के बयान से यही लगता है कि वह भी इस घटना से सगम रहते अवगत नहीं हो सके। यह ठीक है कि मणिपुर में इंटरनेट बंद होने से सूचनाएं देरी से बाहर आ रही थीं, लेकिन जब पुलिस घटना से अवगत थी, तब उसने इतने संगीन मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लिया?

मणिपुर की आहट मिजोरम तक

रहता था जबकि 40 प्रतिशत आबादी वाला कुकी—जोमी समाज 90 प्रतिशत पहाड़ी इलाके में संविधान में मिले अपने विशेष अधिकारों के साथ रहता है। पूरे पूर्वोत्तर में आदिवासी लोगों को सम्य बनाने के लिए ईसाई मिशनरियों ने अंग्रेजी शासनकाल के दौरान ही प्रयास किये और इसके साथ ईसाई ६ र्म भी वहां फैलता गया। इसलिए मणिपुर में मैतई—कुकी संघर्ष के चलते पहाड़ों पर स्थित कम से कम ढाई सौ चर्च या गिरिजाघर भी जला दिये गये जिससे इस संघर्ष को साम्प्रदायिक आयाम भी मिल गया क्योंकि 80 प्रथिशत मैतई समाज हिन्दू धर्म को मानता है। सबसे खतरनाक काम यही हुआ कि यह साम्प्रदायिक रंग में रंग गया जिसके असर से अब पूर्वोत्तर के दूसरे राज्य भी प्रभावित हो रहे हैं। मिजोरम की राजधानी एजेल में सरकारी दफ्तरों से लेकर स्कूलों, कालेजों व निजी कम्पनियों में मैतई समाज के लोग काम करते हैं। इन्हें मिजो नेशनल फ्रंट ने नेतावनी दी है कि वे उनके राज्य से बाहर चले जायें। इसके साथ ही मिजोरम के मिजो जनजाति के लोगों की बहुत समानता भी रही है। इस वजह से मैतई समुदाय के

सबसे पहले हर भारतवासी को यह स्पष्ट होना चाहिए कि पूर्वोत्तर के राज्य भारत माता का ऐसा उज्ज्वल माथा हैं जिसके हर हिस्से के हर राज्य ने प्रत्येक परिस्थिति में राष्ट्र की सुरक्षा में आहुति देने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई है। चीन की सीमा से सटे ये राज्य भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की अग्रिम पंक्ति रहे हैं अतः इनमें पूर्ण शान्ति व सौहार्द बनाये रखने के लिए 1947 से ही भारत की हर केन्द्र सरकार ने गंभीर प्रयास किये हैं और इन राज्यों की उग्रवाद व चरमपंथी समस्याओं का निपटारा भी किया है। 2013 तक पूर्वोत्तर के हर राज्य से चरमपंथ या उग्रवाद की समस्या सफलतापूर्वक समाप्त कर दी गई थी और सभी राज्यों के लोग अपने लोकतान्त्रिक अधिकारों का प्रयोग करके अपनी चुनी हुई सरकारों के माध्यम से अपना विकास कर रहे थे। परन्तु विगत मई महीने के शुरु में इन्ही राज्यों में से एक मणिपुर में यहां की दो जनजातियां मैतई व कुकी—जोमो के बीच जो संघर्ष छिड़ा उससे यह राज्य अब गृहयुद्ध की स्थिति में पहुंचता जा रहा है क्योंकि मई से लेकर अब तक जनजातीय संघर्ष

जिन्हें हम अपने जीवन में क्रियान्वित कर अपने मनुष्य जाति के जीवन को अधिक सार्थक एवं सुलभ बना सकते हैं। निस्संदेह हमें रूढ़ीवादी या एकदम पुरातन पंथी संस्कृति से लगाव न रखकर पाश्चात्य संस्कृति के जो फायदे हैं, उन्हें अपनाकर अपना जीवन सरल सार्थक एवं सुगम बना सकते हैं। परंतु आज वर्तमान के अन्य देशों से विकास की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। भारत में अनेक परंपराएं ऐसी हैं जो सामाजिक जीवन को अधिक सम्य एव अच्छा इसान बनाए रखने में योगदान देती है। जिनसे मनुष्यता का जीवन जीने की प्रेरणा भी मिलती है। यांत्रिक उपकरणों की तरह जिंदगी जीना भी कोई जीना है। यह भारतीय संस्कृति में पाश्चात्य का घालमेल ही है जो मनुष्य के जीवन को यंत्रवत बना देता है। जो आने वाले कल के लिए घातक भी हो सकती है। वहीं दूसरी ओर पाश्चात्य दर्शन की कुछ विशेषताएं भी हैं, जो हमारे विचारों को अधिक तार्किक तथा बौद्धिक बनाती है। जिससे हम अपना जीवन कार्तिक तथा बौद्धिक बना सकते हैं।

उन्हें अपना सकते हैं क्या?, आज जब दुनिया वैज्ञानिक चमत्कारों से भरी पड़ी है। दुनिया विज्ञान की प्रगति से चांद तो क्या सूर्य को भी खंगालने का प्रयास कर रही है। मानव का कलोन बनाकर ईश्वर की सत्ता को चुनौती देने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में धार्मिक संस्कृति तथा आध्यात्मिकता को आवश्यकता से अधिाक महत्व एवं परंपरा में लाना प्रासंगिक एवं तार्किक होगा। निस्संदेह आन एव वैज्ञानिक संस्कृति है। भौतिकता प्रधान युग से तात्पर्य ऐसी परंपरा जो यथार्थवादी दृष्टिकोण को सर्वाधिक महत्व देती है। वैसे ही भौतिकता का सामान्य मतलब इंद्रिय बोध से साक्षात संबंध रखने वाली वस्तु से है, अर्थात जो वास्तविकता एवं देश को महिमामंडित करने में लगे रहते हैं। किंतु आज आवश्यकता इस बात की है कि हमें पूर्ण रूप से आध्यात्मिक ना होकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर इस तथ्य का सही मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि 21 सदी में पांचवी एवं छठवीं सदी की मान्यताएं तथा परंपराएं जारी रख

जिन्हें हम अपने जीवन में क्रियान्वित कर अपने मनुष्य जाति के जीवन को अधिक सार्थक एवं सुलभ बना सकते हैं। निस्संदेह हमें रूढ़ीवादी या एकदम पुरातन पंथी संस्कृति से लगाव न रखकर पाश्चात्य संस्कृति के जो फायदे हैं, उन्हें अपनाकर अपना जीवन सरल सार्थक एवं सुगम बना सकते हैं। परंतु आज वर्तमान के अन्य देशों से विकास की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। भारत में अनेक परंपराएं ऐसी हैं जो सामाजिक जीवन को अधिक सम्य एव अच्छा इसान बनाए रखने में योगदान देती है। जिनसे मनुष्यता का जीवन जीने की प्रेरणा भी मिलती है। यांत्रिक उपकरणों की तरह जिंदगी जीना भी कोई जीना है। यह भारतीय संस्कृति में पाश्चात्य का घालमेल ही है जो मनुष्य के जीवन को यंत्रवत बना देता है। जो आने वाले कल के लिए घातक भी हो सकती है। वहीं दूसरी ओर पाश्चात्य दर्शन की कुछ विशेषताएं भी हैं, जो हमारे विचारों को अधिक तार्किक तथा बौद्धिक बनाती है। जिससे हम अपना जीवन कार्तिक तथा बौद्धिक बना सकते हैं।

प्रश्न यह भी है कि आखिर खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थीं? चार मई की घटना मणिपुर के माहोल को फिर से खराब सकती है, क्योंकि वह बेहद अचानक और विचलित करने वाली है। आज के जमाने में दो समुदायों में इतना वैमनस्य होना चकित करता है। आया और उसे लेकर हड़कंप मचा। किसी के लिए ए भी समझना कठिन है कि घटना की एफआइआर मई में ही हो जाने के बाद भी पुलिस को कार्रवाई करने में इतना समय क्यों लग गया? मणिपुर के मुख्यमंत्री, जो राज्य के गृहमंत्री भी हैं, के बयान से यही लगता है कि वह भी इस घटना से समय रहते अवगत नहीं हो सके।

सुरक्षा बल तैनात किए गए। उन्हें भी स्थिति को नियंत्रित करने में कठिनाई हुई। इस दौरान देश के राजनीतिक दलों को मणिपुर की वस्तुस्थिति से अवगत कराने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री की ओर से एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, लेकिन उसमें आरोप—प्रत्यारोप ही अधिक हुए। विपक्षी दलों ने यह शिकायत की कि इस बैठक में प्रधानमंत्री क्यों नहीं हैं? यह शिकायत यह जानते हुए भी की गई कि वह उस समय अमेरिका के दौरे पर थे। मणिपुर की शर्मनाक घटना का वीडियो सामने आने से विपक्ष सरकार के प्रति हमलावर है। वह संसद नहीं चलने दे रहा है। पक्ष—विपक्ष के बीच इस पर मतभेद है कि मणिपुर पर चर्चा किस नियम के तहत हो। आखिर चर्चा आवश्यक है या फिर कि वह किसे नियम के तहत हो? मणिपुर पर संसद में चर्चा होनी ही

मिजोरम में एक स्थानीय नेताओं के साथ एक बैठक के दौरान मिजोरम के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह के साथ मिजोरम के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह

लोगों को एजोल से हवाई जहाज से वापस मणिपुर लाने के लिए यहां की राज्य सरकार ने हामी भर दी है। क्या यह उस भारत का चित्र है जिस भारत के विभिन्न राज्यों में दूसरे राज्यों के लोग रोजी—रोटी कमाने जाते हैं? संविधान कहता है कि इस देश का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में जाकर बस सकता है और अपना काम—धंधा कर सकता है। इन्ही पूर्वोत्तर के राज्यों में आज भी हजारों मारवाड़ी व्यापारी कार्यरत हैं (बेशक कुछ संरक्षण संविधान ने स्थानीय लोगों को दिये हुए हैं)। गंभीर सवाल मैतई समाज हिन्दू धर्म को मानता है। साम्प्रदायिक आधार और आदिवासी व गैर आदिवासी आधार पर हिंसा फैलने लगी तो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी समस्या हो सकती है। मणिपुर का मसला इसके साथ ही जो अन्तर्राष्ट्रीय आयाम ले रहा है वह भी भारत की सांख के लिए बहुत चिन्ताजनक है क्योंकि मणिपुर की समस्या मूलतः मानवीय समस्या ही है जिसमें एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के खून का प्यासा बना हुआ है। यूरोपीय संघ की संसद से लेकर ब्रिटेन की संसद तक में इस पर चर्चा हो रही है।

जिन्हें हम अपने जीवन में क्रियान्वित कर अपने मनुष्य जाति के जीवन को अधिक सार्थक एवं सुलभ बना सकते हैं। निस्संदेह हमें रूढ़ीवादी या एकदम पुरातन पंथी संस्कृति से लगाव न रखकर पाश्चात्य संस्कृति के जो फायदे हैं, उन्हें अपनाकर अपना जीवन सरल सार्थक एवं सुगम बना सकते हैं। परंतु आज वर्तमान के अन्य देशों से विकास की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। भारत में अनेक परंपराएं ऐसी हैं जो सामाजिक जीवन को अधिक सम्य एव अच्छा इसान बनाए रखने में योगदान देती है। जिनसे मनुष्यता का जीवन जीने की प्रेरणा भी मिलती है। यांत्रिक उपकरणों की तरह जिंदगी जीना भी कोई जीना है। यह भारतीय संस्कृति में पाश्चात्य का घालमेल ही है जो मनुष्य के जीवन को यंत्रवत बना देता है। जो आने वाले कल के लिए घातक भी हो सकती है। वहीं दूसरी ओर पाश्चात्य दर्शन की कुछ विशेषताएं भी हैं, जो हमारे विचारों को अधिक तार्किक तथा बौद्धिक बनाती है। जिससे हम अपना जीवन कार्तिक तथा बौद्धिक बना सकते हैं।

वैसे पाश्चात्य संस्कृति में बहुत सी अहितकर बातें भी हैं, जैसे वसुधैव कुटुंबकम की भावना कमतर होते जा रही है। संयुक्त परिवार की प्रणाली का विघटन होते जा रहा है। पारिवारिक कलह कर लोग परिवार से अलग होकर स्वतंत्र जीवन यापन करना पसंद करते हैं। उनमें विवाह विच्छेद और अल्प विसंगतियां जन्म लेने लगी हैं। धर्म तथा आध्यात्मिक के प्रति आमजन की सूची धीरे धीरे कम होते जा रही है। ऐसेो आराम के सामान खरीदने के कारण लोगों के खर्चे अनाप—शनाप बढ़ चुके हैं। बुजुर्गों की इज्जत तवज्जुतों हानी कम हो गई है। दादा और नाती के संबंधों में अब वह गर्माहट शेष नहीं रह गई है, भी वैज्ञानिक एवं वस्तु परख माना जात है क्योंकि इसमें सूक्ष्म जांच पड़ताल कर वस्तु स्थिति का सही मूल्यांकन अपनाकर एक सामान्य सिद्धांत एवं नियम बनाया जाता है। जिससे भविष्य की बातों को जानकर

जिन्हें हम अपने जीवन में क्रियान्वित कर अपने मनुष्य जाति के जीवन को अधिक सार्थक एवं सुलभ बना सकते हैं। निस्संदेह हमें रूढ़ीवादी या एकदम पुरातन पंथी संस्कृति से लगाव न रखकर पाश्चात्य संस्कृति के जो फायदे हैं, उन्हें अपनाकर अपना जीवन सरल सार्थक एवं सुगम बना सकते हैं। परंतु आज वर्तमान के अन्य देशों से विकास की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। भारत में अनेक परंपराएं ऐसी हैं जो सामाजिक जीवन को अधिक सम्य एव अच्छा इसान बनाए रखने में योगदान देती है। जिनसे मनुष्यता का जीवन जीने की प्रेरणा भी मिलती है। यांत्रिक उपकरणों की तरह जिंदगी जीना भी कोई जीना है। यह भारतीय संस्कृति में पाश्चात्य का घालमेल ही है जो मनुष्य के जीवन को यंत्रवत बना देता है। जो आने वाले कल के लिए घातक भी हो सकती है। वहीं दूसरी ओर पाश्चात्य दर्शन की कुछ विशेषताएं भी हैं, जो हमारे विचारों को अधिक तार्किक तथा बौद्धिक बनाती है। जिससे हम अपना जीवन कार्तिक तथा बौद्धिक बना सकते हैं।

संसद में सार्थक चर्चा करने के बजाय हंगामा करने से किसी राजनीतिक दल को कोई विशेष लाभ मिलता है। इसके बाद भी संसद में एक—दूसरे पर राजनीतिक हमले की कोशिश रहती है। यदि संसद लोकतंत्र का मंदिर है तो फिर वहां जनता की भलाई वाले कामों को लेकर चर्चा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसी तरह विकास के कामों को आगे बढ़ाने तथा सामाजिक सद्भाव को बल देना भी एक साझा उद्देश्य होना चाहिए। जब संसद में सार्थक चर्चा होगी, तभी जनता को कोई सही दिशा मिलेगी और संसद की महत्ता बढ़ेगी। महज एक—दूसरे को नीचा दिखाने वाली राजनीति से राष्ट्र निर्माण की ओर नहीं बढ़ा जा सकता। लगता है राजनीतिक दल यह समझने को तैयार नहीं कि संसद में गंभीर चर्चा लगातार कम होती जा रही है और इसके कारण उसकी जहत्ता और गरिमा प्रमत्तित हो रही है। जब भी संसद का सत्र आयोजित होता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक—दूसरे से उलझते ही दिखते हैं। विपक्ष कई बार चर्चा की मांग भी करता है और सदन भी नहीं चलने देता। संसद न चलने से केवल लोकतंत्र ही कमजोर नहीं होता, बल्कि देश की प्रगति भी रुकती है, क्योंकि कई आवश्यक विधेयक समय रहते पारित नहीं हो पाते। प्रधानमंत्री मोदी ने ठीक ही कहा कि यह सभ्य समाज को शर्मसार करने वाली घटना है और इससे पूरे देश की बेइज्जती हो रही है। इस शर्मनाक घटना में आश्चर्य की बात यह है कि पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने में जरूरत से ज्यादा समय लगा दिया। दोषियों की गिरफ्तारी करीब दो माह बाद तब की गई, जब घटना का वीडियो सामने आया और उसे लेकर हड़कंप मचा। किसी के लिए भी समझना कठिन है कि घटना की एफआइआर मई में ही हो जाने के बाद भी पुलिस को कार्रवाई करने में इतना समय क्यों लग गया? मणिपुर के मुख्यमंत्री, जो राज्य के गृहमंत्री भी हैं, के बयान से यही लगता है कि वह भी इस घटना से समय रहते अवगत नहीं हो सके।

मिजोरम में एक स्थानीय नेताओं के साथ एक बैठक के दौरान मिजोरम के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह के साथ मिजोरम के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह

माध्यमिक शिक्षक संघ जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर संपन्न हुआ



जौनपुर ब्यूरो
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जौनपुर का एकदिवसीय धरना जिलाध्यक्ष सुधाकर सिंह के नेतृत्व में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर संपन्न हुआ इसमें प्रदेश अध्यक्ष चेतनारायण सिंह के साथ बड़ी संख्या में माध्यमिक शिक्षक शामिल हुए। धरने में कई अन्य संगठनों के प्रतिनिधि समर्थन देने के लिए पहुंचे। जिलामंत्री प्रमोद कुमार सिंह ने धरने के मुद्दों का वाचन

व्यावसायिक एवम कंप्यूटर शिक्षकों को शिक्षक पदों पर समायोजित करना जैसे मुद्दों को लेकर किया जा रहा है।

प्रदेश अध्यक्ष चेतनारायण सिंह ने धरने में लोगों की बड़ी संख्या में भागीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त की तथा दिल्ली के रामलीला मैदान में 10 अगस्त को होने वाली रैली एवं संसद मार्च के लिए लोगों से बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील की।

प्रदेश उपाध्यक्ष नरसिंह बहादुर सिंह ने कार्यालय को चेताया कि किसी भी स्थिति में शिक्षकों के कार्यों में हीलाहवाली बर्दास्त नहीं की जाएगी। प्रदेश मंत्री अजय प्रकाश सिंह ने विश्वास व्यक्त किया कि संघर्ष के बल पर पुरानी पेंशन शीघ्र प्राप्त हो जाएगी।

जिलाध्यक्ष सुधाकर सिंह ने आए हुए सभी शिक्षकों का आभार व्यक्त किया। इस धरने को दिनेश चक्रवर्ती, जयप्रकाश सिंह, रामप्रकाश

सहोदय स्कूल्स कॉम्प्लेक्स लखनऊ चौप्टर द्वारा गोयल कैम्पस में आयोजन



ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय लखनऊ। सहोदय स्कूल्स कॉम्प्लेक्स लखनऊ चौप्टर के माध्यम से २५ जुलाई २०२३ को प्रातः १० बजे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी

लगभग ८० से ज्यादा शिक्षक-शिक्षिकाओं ने भाग लिया। सम्मेलन का शुभारम्भ मुख्य अतिथि जावेद आलम खान (चेयरपर्सन ऑफ कोऑर्डिनेटर, प्रिंसीपलध्वजोईंट डायरेक्टर ऑफ लखनऊ पब्लिक कॉलेजिएट), बी. सिंह (सेक्रेट्री सीबीएसई सहोदय) गोयल ग्रुप ऑफ अग्रवाल, विद्यालय की प्रधानाचार्या डॉ. रीना पाठक के करकमलों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। शिक्षा जगत में पिछले २३ सालों से अपना योगदान देने वाली, विरिष्ठ शिक्षाविद श्वेता खन्ना ने आयोजन की अध्यक्षता करते हुए वर्तमान समय में एनईपी के उद्देश्यों से सभी को

15 राज्यों से आए 111 से अधिक प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया

समाज में जो अंधकार छाया हुआ है उसको प्रकाश में करने के लिए नंदिनी शिविर की बड़ी भूमिका है : रमेश भड़वा बहने रचनात्मक कार्यक्रमों को अपनाकर समाज के सेवा कार्यों का दायित्व संभालें: सुधीर भाई



ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय उज्जैन। 'अंकित ग्राम' सेवाधाम के परोक्ष समाजसेवी मास्टर अंकित गोयल के 39वें जयन्ती पर्व पर 39 दिवसीय 32वें वर्षा मंगल महोत्सव "अंकितग्राम वर्षा मंगल राष्ट्रोत्सव" का तीन दिवसीय नंदिनी लोकमित्र राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन सत्र सम्पन्न हुआ जिसमें देश के आए हुए 111 समाजसेवियों को मान पत्र एवं प्रशस्ति पत्र से गांधी-विनोबा के विचारों को जनमानस में प्रवाहित करने हेतु सम्मानित किया गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि अंकितग्राम, सेवाधाम आश्रम संस्थापक सुधीर भाई ने कहा कि आज इतनी महिलाएँ देश के कोने-कोने से सेवाधाम आश्रम में आ सकती हैं तीन दिन रुककर नंदिनी लोकमित्र राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग ले सकती हैं इतनी कल्पना करना हमारे लिए मुश्किल था क्योंकि अकेला आदमी भी कहीं जाने में कई



सेवा आश्रम, शाहजहांपुर ने कहा कि अंधकार को ना धिक्कारे, अच्छा है दीप जलाए इसी परम्परा को देशभर में बहने निर्वाह करेंगी। इस दृष्टि से तीन दिन का नंदिनी सम्मेलन सफल माना जा सकता है क्योंकि यहां जो बहनों ने संकल्प लिया है उनमें साफ झलकता है जहां-जहां भी समाज में अंधेरा दिखेगा यह नंदिनी बहनें अपनी सेवा का प्रकाश फैलाएंगी। बाबा कहा करते थे कि कितना भी घनघोर अंधेरा हो लेकिन दीपक जलाने से उस स्थान पर तो उजाला हो ही जाता है। अब तक नंदिनी शिविर के माध्यम से हजारों बहनें दिपक बन चुकी हैं जो कभी न कभी समाज में रोशनी फैलाने वाले सूर्य को अवकाश अवश्य देंगी, मातृ शक्ति पौषण-सृजन और रचना की प्रतीक है, समाज को इन तीनों माध्यमों की जरूरत है। समारोह की अध्यक्षता श्रीमती कांता भाभी, विमला बहन ने की एवं इस अवसर पर

सावन का तीसरा सोमवार, शिवभक्तों पर योगी सरकार ने कराई पुष्पवर्षा

संवाददाता लखनऊ। सावन में प्रदेश में शिवभक्त कांठियों पर पुष्पवर्षा का क्रम तीसरे सोमवार को भी जारी रहा। सावन के पिछले दो सोमवार को काशी, मेरठ और सहारनपुर में पुष्पवर्षा की गई। तीसरे सोमवार को बाराबंकी स्थित लोधेश्वर महादेव मंदिर में हेलीकॉप्टर द्वारा कांवरियों पर पुष्प वर्षा की गई। इसके अलावा अयोध्या में भी सूर्योदय पर शिवभक्तों पर योगी

सरकार ने पुष्पवर्षा कराई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पिछले 6 साल से प्रदेश में शिवभक्तों का खास तरीके से सम्मान किया जा रहा है। सरकार की ओर से ना सिर्फ कांठियों पर

मणिपुर के हालात के जिम्मेदार मुख्यमंत्री बीरेन सिंह दे इस्तीफा

संवाददाता लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन जरूरतमंदों को अभी पक्का मकान नहीं मिल पाया है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के दायरे में लाकर पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। योगी ने यहां जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनीं और मौजूद अधिकारियों को उसके निराकरण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस से संबंधित मामलों में प्रभावी कार्रवाई हो और साथ ही अवैध कब्जा करने वालों को कड़ा कानूनी सबक सिखाया जाए। अधिकारी जन कल्याण के कार्यों को सदैव प्राथमिकता पर रखें और हर पीड़ित की समस्या का तुरंत निराकरण करना सुनिश्चित करें। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने करीब 500 लोगों की समस्याएं सुनीं। इसमें बड़ी संख्या महिलाओं की रही। इस दौरान देवरिया से आई एक महिला ने आवास की समस्या बताई।

सामूहिक बलात्कार की शिकार महिलाओं, जिन्होंने नंगे कपड़ों में सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन किया, के बाद वह धोखा देकर चले गये। भाजपा सरकार ने चुराचांदपुर वन क्षेत्र के 38 कुकी आदिवासी गांवों को अवैध बस्तियों के रूप में चिह्नित किया और कहा कि वहां रहने वाले कुकी वन भूमि में अतिक्रमणकारी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोप लगाया है कि मणिपुर राज्य में महिलाओं के नग्न मार्च, सामूहिक से पहाड़ी लोगों को संविधान के अनुच्छेद 371 (सी) के तहत दी गई स्वायत्त शक्ति वापस लेने की केंद्र सरकार की साजिश है और इसके पीछे पहाड़ी लोगों के वन भूमि अधिकारों को दबाने की योजना है। उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव में केंद्रीय

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भरपूर लाभ उठाये किसान : शाही

जागरूकता अभियान चलाने के लिए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

संवाददाता लखनऊ। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से संचालित फ्लैगशिप योजना "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" के व्यापक प्रचार-प्रसार करने, योजना के प्रति कृषकों की आशंकाओं के समाधान करने एवं योजना में कृषकों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि भवन में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया। योजना की जागरूकता का कार्यक्रम प्रदेश में पूरे जुलाई माह में चलाया जाएगा। अभियान संबोधन में सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि आपदा के समय कृषकों की आय को स्थिर रखने

एवं कृषकों की आय दुगुनी करने की दिशा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक महत्वपूर्ण स्तम्भ है। यह कृषकों को किसी भी प्रकार की दैवीय आपदा के विरुद्ध उनकी अधिसूचित फसलों को बीमा कवर प्रदान करते हुए वित्तीय सहायता प्रदान करती है और उन्हें कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीक, आधुनिक संसाधन एवं उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग कर उत्पादन को बढ़ाये जाने हेतु प्रोत्साहित करती है। बीमित कृषक न केवल अपनी आय में वृद्धि करता है बल्कि प्रदेश एवं देश की खाद्यान्न सुरक्षा में अपने योगदान की प्रमुखता को बनाये रखता है। आज कृषि जगत में सबसे बड़ी चुनौती, जो किसान भाइयों के सामने है, वह है जलवायु परिवर्तन। समय से वर्षा न

करने वालों में सीतापुर के राम अचल को 1.67 लाख रुपये, ललितपुर के राजेन्द्र सिंह को 1.34 लाख रुपये, बाराबंकी के विक्रमजीत सिंह को 1.26 लाख रुपये, सीतापुर के सावली प्रसाद को 1.25 लाख रुपये, बाराबंकी के कौशलेश्वर प्रताप सिंह को 1.23 लाख रुपये, वाराणसी के रामबली मिश्र को 1.22 लाख रुपये, दिनेश सिंह को 1.21 लाख रुपये तथा बाराबंकी के रामगोपाल, माधुरी, यदुनन्दन को क्रमशः 1.18 लाख रुपये, 1.14 लाख रुपये व 1.13 लाख रुपये का बीमा प्राप्त करने वाले किसान शामिल हैं। सांस्कृतिक दल द्वारा प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना पर एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर योजना की सभी जानकारियां बहुत रोचक ढंग से प्रस्तुत की गयीं।

दामन थाम लिया। इनमें सबसे बड़ा नाम है पूर्व सांसद अंशुल वर्मा का। जो दारा सिंह चौहान की तरह एक बार फिर बीजेपी में घर वापसी किए हैं। दरअसल, 2014 में अंशुल वर्मा ने बीजेपी के टिकट पर हरदोई से लोकसभा का चुनाव जीता, सांसद चुने गए। लेकिन 2019 में जब पार्टी ने उनका टिकट काट दिया तो वो सपा की साइकिल पर सवार हो गए थे।

कुरान पाक इंसान के दिल का नूर है : मौलाना खालिद रशीद

संवाददाता लखनऊ। कुरान करीम दुनिया की एक अकेली ऐसी किताब है जिसके हरुफ (अक्षर) और आयतों में क्या इसके जबर उभर और नुकतों में भी कोई बदलाव नहीं कर सकता। इस लिए कि इसकी हिफाजत की पूरी जिम्मेदारी खुदा पाक ने खुद ले रखी है। कुरान पाक में इशराह है कि हमने कुरान नालिज किया है और हम ही उसके मुहाफिज हैं। इन शब्दों का इजहार इमाम ईदगाह लखनऊ मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली नाजिम दारूल उलूम निजामिया फरंगी महल ने किया। वह आज इस्लामिक सेन्टर आफ इण्डिया फरंगी महल के तत्वाधान में होने वाले दस दिवसीय जलसाहाय "शुहादाये दीने हक व इस्लाहे माआशरह" के अर्न्तगत दारूल उलूम फरंगी महल में पांचवें जलसे को संबोधित कर रहे थे।

15 बड़े विपक्षी नेता भाजपा में शामिल हुए, अंशुल वर्मा ने भी की घर वापसी

संवाददाता लखनऊ। आगामी लोक सभा चुनाव से पहले यूपी की सियासत में बड़ा हलचल देखने को मिल रहा है, दरअसल भाजपा ने यूपी की 80 सीटें जीतने के लिए हर पैतरे का इस्तेमाल कर रही है। इसके साथ ही भाजपा ने मिशन डिमॉलिशन का आगाज भी कर दिया है। इस मिशन का सिलसिला दारा सिंह चौहान से शुरू हुआ था, लेकिन आज देखा जा रहा है कि बीजेपी विपक्षी दलों में सर्जिकल स्ट्राइक करती हुई नजर आ रही है। इस स्ट्राइक का सबूत आज यानि सोमवार को लखनऊ के पार्टी कार्यालय में देखने को मिला, जहां 15 से अधिक बड़े-बड़े नेताओं ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के सामने भारतीय जनता का

यूपी में रेव पार्टी में हो रही ड्रग्स सप्लाई

संवाददाता लखनऊ। यूपी में युवाओं पर ड्रग्स का नशा सिर चढ़कर बोल रहा है। 24 जून को सुरशांत गोल्फ सिटी के एक पलैट में नाबालिग लड़के-लड़कियों को रेव पार्टी करते हुए पकड़ा गया था। ऐसे ही युवाओं को रेव पार्टी के लिए मादक पदार्थ और ड्रग्स सप्लाई करने वाली एक युवती समेत चार लोगों को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 6.57 लाख रुपए नकद और कार बरामद हुई हैं। यह लोग होटल, फार्म हाउस, घरों और मांग के हिसाब से माल पहुंचाते थे। एसटीएफ इस गिरोह के मुख्य सप्लायर और उससे जुड़े अन्य लोगों की तलाश में छापेमारी कर रही है। एसटीएफ ने मुखबिर की सूचना पर मनकामेश्वर मंदिर के पीछे रहने वाली स्वस्तिका के साथ उसके साथी लखनऊ तेज कुमार प्लाजा निवासी तरुण अवस्थी, कैसरबाग सोनवाली के पीछे रहने वाले पंकज सोनवार और गोमतीनगर विराजखंड निवासी

अजमल को पकड़ा है। यह लोग गोमतीनगर स्थित होटल एसबीजी गेस्ट इन में ड्रग्स की सप्लाई करने के लिए पहुंचे थे। एसटीएफ की टीम इन लोगों की विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर 16 जुलाई को एक वीडियो और कुछ फोटो वायरल होने पर सक्रिय हुई थी। इसमें कुछ लड़के और एक लड़की किसी रूम में बैठकर नोटों की गिनती कर रहे हैं तथा नजदीक में ही शराब की बोतलें और हुक्का रखा हुआ है। एसटीएफ की पूछताछ में पंकज सोनवार ने बताया, आर्यन नाम का युवक मोबाइल फोन से विभिन्न एप्लिकेशन के माध्यम से इंटरनेशनल स्तर पर अवैध मादक पदार्थ एवं ड्रग्स की खरीद फरोख्त करते थे। इसके समान की डिलीवरी हम लोग करते थे। 16 जुलाई को आर्यन और लकी ने होटल राजधानी में कमरा नंबर 104 बुक कराया था। जहां हम लोगों ने नशे की बिक्री के पैसों की गिनती की और हुक्काधाराब की पार्टी की। इसका आर्यन ने इंस्टाग्राम

जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनी फरियाद

संवाददाता लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन जरूरतमंदों को अभी पक्का मकान नहीं मिल पाया है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के दायरे में लाकर पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। योगी ने यहां जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनीं और मौजूद अधिकारियों को उसके निराकरण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस से संबंधित मामलों में प्रभावी कार्रवाई हो और साथ ही अवैध कब्जा करने वालों को कड़ा कानूनी सबक सिखाया जाए। अधिकारी जन कल्याण के कार्यों को सदैव प्राथमिकता पर रखें और हर पीड़ित की समस्या का तुरंत निराकरण करना सुनिश्चित करें। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने करीब 500 लोगों की समस्याएं सुनीं। इसमें बड़ी संख्या महिलाओं की रही। इस दौरान देवरिया से आई एक महिला ने आवास की

समाहिक बलात्कार की शिकार महिलाओं, जिन्होंने नंगे कपड़ों में सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन किया, के बाद वह धोखा देकर चले गये। भाजपा सरकार ने चुराचांदपुर वन क्षेत्र के 38 कुकी आदिवासी गांवों को अवैध बस्तियों के रूप में चिह्नित किया और कहा कि वहां रहने वाले कुकी वन भूमि में अतिक्रमणकारी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोप लगाया है कि मणिपुर राज्य में महिलाओं के नग्न मार्च, सामूहिक से पहाड़ी लोगों को संविधान के अनुच्छेद 371 (सी) के तहत दी गई स्वायत्त शक्ति वापस लेने की केंद्र सरकार की साजिश है और इसके पीछे पहाड़ी लोगों के वन भूमि अधिकारों को दबाने की योजना है। उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव में केंद्रीय

